हिन्दी सान्ध्य दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 01 अंक : 288 : जौनपुर, गुरुवार 20 जुलाई 2023 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज - 4 मूल्य : 2 रूपया

1.91 करोड़ छात्रों को योगी ने दिए 1200 रुपए

एजेन्सी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्रेस दिए। परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्टेशनरी के लिए अभिभावकों के खाते में क्ठज से धनराशि भी भेजी गई। 1.91 करोड़ छात्रों तक 1200 रुपए भेजे गए। इस दौरान 125 कस्तूरबा गांधी विद्यालय का लोकार्पण भी ब्ड योगी ने किया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि भी दी गई। यह राशि निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए सीधे अभिभावकों के खाते में भेजी गई। इससे पहले स्कूल के बच्चों को मिलने वाले ड्रेस को लेकर काफी शिकायतें रहती थीं, लेकिन उन शिकायतों को दूर करने के लिए अब डीबीटी माध्यम का उपयोग किया जाता है। सीएम योगी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को गरीबी से मुक्त करने के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिली है, वह बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में जो लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं वो सक्षम हुए हैं। नीति आयोग ने जो पैरामीटर तय किए थे, उसमें सबसे पहला

पैरामीटर शिक्षा ही था। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं और आने वाले 5–10 साल में इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। सीएम योगी ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से जो पैसा यूनिफॉर्म, जूते–मोजे और स्टेशनरी के लिए भेजा गया है, उसमें हमारे शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि बच्चे नियमित रूप से यूनिफॉर्म में स्कूल आएं। उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक बच्चे के लिए यूनिफॉर्म बनवाने को अभिभावक के साथ बैठक कर चर्चा करेगा, ताकि समयसीमा में बच्चे यूनिफॉर्म, किताबें, जूते–मोजे पा सकें। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले की स्थिति क्या थी, शिक्षकों की भारी कमी थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 वर्ष से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। पिछले 6 वर्ष में एक लाख 64 हजार शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम योगी ने उन संस्थानों का धन्यवाद किया जिन्होंने सीएसआर के मद में बेसिक शिक्षा परिषद के ऑपरेशन कायाकल्प को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ऐसे 6 संस्थानों को उन्होंने सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के साथ–साथ अनेक समाज से जुड़े लोगों ने भी रुचि लेकर ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयां दी हैं।

उन्होंने कहा कि पहले कोई बेसिक शिक्षा परिषद को धनराशि देने की बात करता था क्या, आज 250 करोड़ की सीएसआर की राशि मिली है। इन दानदाताओं के लिए पहले भी व्यवस्था थी, लेकिन कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोई नेतृत्व देने को तैयार नहीं था। उन्होंने विश्वास जताया कि सीएसआर की निधि से इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। इससे हम अपनी नींव को मजबूत करेंगे।

इस अवसर पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा संदीप सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया, हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत अध्यनरत 1.91 करोड़ छात्रों तक 1200 रुपए भेजे गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर पर सभी पार्षदीय विद्यालय को विकसित किया गया। आने वाले समय में समाज के सभी विद्यालय इन सुविधाओं से लैस होंगे।

समय के साथ शिक्षा को बेहतर बनाया जाए और उसमें गुणात्मक सुधार हो, इसके लिए हम सब पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हो रहा है शिक्षा संस्थानों का विस्तार सुंदरीकरण हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा में अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिन से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा मिले। सहयोगी अनुदान की व्यवस्था से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों के लिए भी अनेकों काम किए गए हैं। संस्कृत में शिक्षा का विकास किया गया है।

संसद के समक्ष भूख हड़ताल करेंगे ईपीएस-95 पेंशनभोगी

एजेन्सी

नयी दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि–95 (ईपीएस–95) के पेंशनभोगी पेंशन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर मानसून सत्र को देखते हुए गुरुवार को संसद के समक्ष और देशभर में भूख हड़ताल करेंगे। ईपीएस–95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बुधवार को यहां बताया कि 20 जुलाई को समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य संसद के समक्ष जंतर–मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। इनके समर्थन में देश भर के पेंशनभोगी प्रमुख स्थानों पर भूख हड़ताल पर रहेंगे। कल ही संसद का मानसून सत्र आरंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहद कम पेंशन राशि के कारण गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पेंशनभोगी बहुत ही कम पेंशन के कारण संकटपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं और अपने परिवार और समाज में अपनी गरिमा खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता के कल्याण के लिए कई पेंशन योजनाएं लागू की हैं, लेकिन इन ईपीएस कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा के दौरान पेंशन निधि में योगदान करने के बाद केवल नाममात्र की पेंशन राशि मिल रही है। अशोक राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दो बैठकों और आश्वासन तथा निर्देश प्राप्त करने के बावजूद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की नकारात्मक भूमिका के कारण ईपीएस–95 पेंशनभोगियों की मांगों को मंजूरी नहीं दी गई। समिति ने कहा है कि न्यूनतम पेंशन राशि को जीवन–यापन भत्ते के साथ बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह की जानी चाहिए। यह मांग कोश्यारी समिति (राज्यसभा याचिका 147) की सिफारिश के अनुरूप है। सभी ईपीएस–95 पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए।

नीतीश विपक्षी एकता के सूत्रधार, सूत्रधार नाराज नहीं होते : ललन सिंह

एजेन्सी

पटना। विपक्षी दलों की बेंगलुरु की बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों का पुरजोर खंडन करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बुधवार को कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। उन्होंने कहा कि सूत्रधार कभी नाराज नहीं होते। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ललन सिंह ने इन खबरों को दुष्प्रचार बताया। मीडिया के एक वर्ग को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया वर्ग दुष्प्रचार में लगा हुआ है। पहले जदयू का राजद में विलय उसके बाद जदयू और राजद में खटपट भी इसी दुष्प्रचार का अंग था। अब नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर चलाई जा रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि काहे की नाराजगी।

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया सबकी सहमति से रखा गया है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा को लेकर ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि अभी इस मामले को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है।

विपक्ष का इंडिया सफल नहीं होगा असम के मंत्री केशब महंत

एजेन्सी

नयी दिल्ली। असम के मंत्री केशब महंत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्ष द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) की आलोचना की है और कहा है कि यह सफल नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा, उनके गठबंधन को श्इंडियाश नाम देने से कुछ नहीं होगा। हमें देखना होगा कि इसके अंदर क्या है।

हम अब विपक्ष नहीं, 'इंडिया पार्टी हैं...संसद चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की : जयराम रमेश

एजेन्सी

नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने संसद के मानसून सत्र के आरंभ होने से एक दिन पहले बुधवार को कहा कि मणिपुर हिंसा और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष कोई समझौता नहीं कर सकता तथा संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने 'पीटीआई–भाषाश को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि कांग्रेस दिल्ली से संबंधित केंद्र के अध्यादेश के स्थान पर लाए जाने वाले विधेयक का विरोध करेगी, क्योंकि यह एक चुनी हुई सरकार के संवैधानिक अधिकारों पर अंकुश लगाने वाला है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस संसद चलाने के लिए रचनात्मक सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार को 'माई वे या हाईवेश वाला रवैया छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जवाब और गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय करने की मांग भी की जाएगी। रमेश के मुताबिक, संसद के मानसून सत्र से पहले 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंसश (इंडिया) के बनने के बाद विपक्षी दलों का उत्साह बढ़ा है और नयी उमंग पैदा हुई है। कांग्रेस नेता ने संसद सत्र के लिए 'इंडिया की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''26 पार्टियों के गठबंधन की कल बेंगलुरु में हुई बैठक में काफी लंबी चर्चा हुई कि किन–किन मुद्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए। प्राथमिकता मणिपुर है। मणिपुर में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का कोई असर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह बिल्कुल विफल है। रमेश ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं है...प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए और सांसदों को विश्वास में लेना चाहिए।श्श कांग्रेस नेता के अनुसार, 'संघीय ढांचे पर रोजाना हो रहे आक्रमण, बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई पर भी आगामी सत्र में चर्चा की मांग की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि संसद में गतिरोध की स्थिति से बचने के लिए क्या किया जा सकता है तो रमेश ने कहा, ''हम रचनात्मक सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन संसद चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार कहती है कि 'माई वे या हाईवे, तो कैसे होगा...आम सहमति बनानी पड़ेगी। ताली दोनों हाथ से बजती है। हम रचनात्मक सहयोग करेंगे। दिल्ली से जुड़े केंद्र के अध्यादेश को लेकर रमेश ने कहा कि इससे संबंधित विधेयक का समर्थन करने का तो सवाल ही नहीं उठता।

अपना 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे विराट कोहली

एजेन्सी

नयी दिल्ली। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान अपना 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे। सर्वाधिक रन बनाने की सूची में छठे और अंतरराष्ट्रीय शतकों में केवल सचिन तेंदुलकर से पीछे, कोहली 500 मैचों की उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय होंगे। जियोसिनेमा विशेषज्ञ आकाश चोपड़ा ने कोहली की उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना की और उन्हें खेल का ब्रांड एंबेसडर करार दिया।"विराट कोहली का खेल के प्रति समर्पण बहुत स्पष्ट है और जो वास्तव में उन्हें परिभाषित करता है। जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन एक संन्यासी की तरह जीया है जहां बात सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित रही है यही कारण है कि वह आज इस मुकाम पर हैं और इस खूबसूरत खेल के ब्रांड एंबेसडर हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट और सामान्य तौर पर क्रिकेट के लिए जो किया है, उसके लिए हम सभी आभारी हैं। प्रज्ञान ओझा ने भी उनकी प्रशंसा की और इसे श्एक और उपलब्धि वाला क्षण बताया, ष्यह एक बहुत ही विशेष उपलब्धि है। बहुत कम लोग ही यह उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह उनके लिए प्रेरणा का काम करेगा और वह देश के लिए अच्छी पारियां खेलते रहेंगे और अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखेंगे। वसीम जाफर ने कोहली की लंबी उम्र की सराहना की और कहा, "हर किसी को 500 मैच खेलने का मौका नहीं मिलता है और उनकी लंबी उम्र प्रशंसनीय है–जिस तरह से उन्होंने खुद को फिट और लगातार बनाए रखा है और अच्छा खेलना जारी रखा है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 75 शतक बनाए हैं।

तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, हाई कोर्ट का फैसला किया रद्द

एजेन्सी

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने नियमित जमानत के लिए सीतलवाड़ की याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीतलवाड़ के खिलाफ मामले में आरोपपत्र दायर कर दिया गया है और उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा, ''अपीलकर्ता का पासपोर्ट पहले ही जमा किया जा चुका है, जो सत्र अदालत के पास रहेगा। अपीलकर्ता गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी और उनसे दूर रहेंगी। पीठ ने गुजरात पुलिस को यह छूट दी कि यदि मामले में गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो वह सीधे शीर्ष अदालत आ सकती है। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के आरोप में सीतलवाड़ को पिछले साल 25 जून को गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के साथ अहमदाबाद अपराध शाखा पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में हिरासत में लिया गया था। अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने 30 जुलाई, 2022 को सीतलवाड़ और श्रीकुमार की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वालों के लिए यह संदेश जाएगा कि कोई व्यक्ति आरोप लगा सकता है और दंड से बच सकता है। उच्च न्यायालय ने तीन अगस्त, 2022 को सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था और मामले की सुनवाई 19 सितंबर को तय की थी। इस बीच, सीतलवाड़ ने उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद अंतरिम जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल दो सितंबर को सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी थी और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला करने तक अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने को कहा था।

तृणमूल कांग्रेस की तथ्यान्वेषी टीम मणिपुर के लिए रवाना

एजेन्सी

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की पांच सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम हिंसा प्रभावित राज्य की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुधवार को मणिपुर के लिए रवाना हुई।

इम्फाल के लिए रवाना होने से पहले, टीम के सदस्यों ने उन्हें संघर्ष प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने से रोकने के लिए मणिपुर में स्थानीय प्रशासन से असहयोग की आशंका व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने कहा, "हम संसद के अगले सत्र से पहले मणिपुर के अशांत क्षेत्रों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें संदेह है कि क्या हम उन सभी आदिवासी इलाकों का दौरा कर पाएंगे जहां हिंसा भड़की थी।

एक बार फिर पेशाब कांड आंध्र के आदिवासी युवक से मारपीट और चेहरे पर किया पेशाब

एजेन्सी

अमरावती। आंध्र प्रदेश में एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट करने के बाद उसके चेहरे पर पेशाब करने वाले युवकों के एक समूह की शर्मनाक हरकत सामने आई है।

करीब एक महीने पहले प्रकाशम जिले के ओंगोल शहर में हुई घटना का चौंकाने वाला वीडियो बुधवार को सामने आया।

यह घटना आरोपी और पीड़ित के बीच प्रतिद्वंद्विता का नतीजा थी। आरोपी और पीड़ित दोनों ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति द्वारा एक आदिवासी मजदूर पर पेशाब करने की घटना के ठीक बाद ओंगोल की घटना ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और आदिवासी समूहों ने कार्रवाई की मांग की है। करीब एक महीना पहले नौ युवकों के एक समूह ने नवीन नामक व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में, नवीन खून से लथपथ है और वह हमलावरों से छोड़ देने की गुहार लगा रहा है। कुछ आरोपियों ने नवीन के चेहरे पर पेशाब कर दिया और उसे पीने के लिए कहा।

ओंगोल पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी फरार है। इस मामले का मुख्य आरोपी रामानंजेयुलु उर्फ अंजी है जो नवीन का बचपन का दोस्त बताया जा रहा है। दोनों चोरी के 50 से अधिक मामलों में शामिल हैं।

नवीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कुछ मामलों में जेल भेज दिया था, जबकि अंजी किसी तरह पुलिस के जाल से भागने में सफल रहा था। हाल ही में उनके बीच मतभेद हो गया।

करीब एक महीने पहले अंजी ने नवीन को केआईएमएस मेडिकल कॉलेज के पीछे बुलाया। जब नवीन वहां पहुंचा तो अंजी आठ अन्य लोगों के साथ मौजूद था। उनके बीच तीखी बहस हुई। नशे में धुत हमलावरों ने नवीन की बेरहमी से पिटाई की। जब वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया तो तीन अपराधियों ने उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया।

उन्होंने अपने कृत्य को मोबाइल फोन पर कैद किया। वे वीडियो में पीड़ित से पेशाब पीने के लिए कहते सुने जा सकते हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

भाजपा का सीएम पर निशाना, कहा, गहलोत ने राजस्थान को 'शर्मसार कर दिया

एजेन्सी

जयपुर। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की हाल की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य को 'बदनाम और शर्मसार कर दिया है। पार्टी ने यह दावा भी किया कि कांग्रेस का हर विधायक अधिकारियों के तबादले और तैनाती को नियंत्रित करता है इसलिए अपराध की घटनाओं से जुड़े मामलों में कार्रवाई की संभावना समाप्त हो जाती है। यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में पिछले दिनों एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई लेकिन गहलोत इस प्रकरण पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहें। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में जितनी भी बलात्कार और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हुईं, विशेष तौर से दलित महिलाओं के साथ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, ''इसके पीछे भी वह (गहलोत) विचारधारा और तुष्टिकरण की नीति देख रहे हैं। अशोक गहलोत को लग रहा है कि मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वहां जो भी घटनाएं महिलाओं, दलितों और आदिवासी समाज के साथ हो रही हैं, उससे आपका वोट बैंक खिसक चुका है।

मेघवाल ने कहा, ''जिस तरीके से राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं और कांग्रेस तथा गहलोत सरकार की ऐसे मामलों में जो नीति रही है... तुष्टिकरण और वोट बैंक की नीति के चलते उन्होंने राजस्थान को आज अशांत, बदनाम और शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून–व्यवस्था का हाल यह है कि कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने बयान दिया है कि वह खुद सुरक्षित नहीं महसूस करतीं। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस के राज में कांग्रेस के विधायक ही डर रहे हैं तो फिर जनता का क्या होगा। मेघवाल ने आरोप लगाया, ''गहलोत राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुख्य कारण हैं। वह कहते रहते हैं कि विधायकों ने उनकी सरकार बचा ली है। इससे उनका समर्थन करने वाले विधायक खुद मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे पुलिस और यहां तक कि जिला कलेक्टरों समेत अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती को नियंत्रित करते हैं। वे भ्रष्ट हो गए हैं। मेघवाल ने दावा किया कि भाजपा सुशासन और विकास की पक्षधर है जबकि कांग्रेस की प्राथमिकता तुष्टिकरण और वोट बैंक है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी मानहानि के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के विरोध में श्मौन व्रतश रखती है लेकिन अपराधों के ऐसे गंभीर मामलों पर कुछ नहीं करती।

सम्पादकीय

इंडिया बनाम भाजपा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के उद्देश्य से कांग्रेस की अगुवाई में 26 विपक्षी दल एकत्र हुए और अब इस मोर्चे का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखा गया है। वहीं अपने किले को प्रतिपक्षी आक्रमण से बचाने के लिये भाजपा ने छोटी–बड़ी 38 सियासी पार्टियों को अपने पक्ष में लामबन्द किया है। विपक्षी दलों के मुकाबले 12 अधिक दलों का समर्थन जुटाकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा (एनडीए) ने खुद की छतरी बड़ी दिखलाने की कोशिश की है परन्तु दोनों के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है तभी इस परिघटना के महत्व और भावी राजनैतिक परिदृश्य को गहराई से समझा जा सकता है। वैसे तो एक लम्बे समय से यह माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का न तो कोई विकल्प है और न ही भाजपा को हराया जा सकता है। पिछले साल की मई के दूसरे हफ्ते में कांग्रेस की उदयपुर में हुई संकल्प बैठक में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने खुद को रिचार्ज किया। इस बैठक में लिये गये निर्णय के ही मुताबिक राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से 7 सितम्बर, 2022 को एक लम्बी दूरी की पैदल यात्रा प्रारम्भ की जिसके 30 जनवरी, 2023 को कश्मीर (श्रीनगर) पहुंचते–पहुंचते भारत की राजनैतिक तस्वीर बदलने लगी। यात्रा के दौरान व संसद में और तत्पश्चात इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से राहुल ने मोदी पर हमला बोला, उन्हें पहले अवमानना के एक छोटे से मामले में सजा दिलाई गई। बुलेट ट्रेन की गति से उनकी सांसदी छिन गई तथा उनका शासकीय बंगला खाली कराया गया। इसके बाद तो देश की फिजा ही बदल गई। जो कांग्रेस पहले कई दलों के लिये अस्वीकार्य ही नहीं त्याज्य भी थी, उसमें उन्हें भाजपा के खिलाफ लड़ाई की रहनुमाई के तत्व दिखने लगे। बेंगलुरु में विपक्षी दलों के इस महाजुटान में परस्पर विमर्श कर भाजपा को अगले साल के आम चुनाव के जरिये सत्ताच्युत करने सम्बन्धी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। अब इंडिया की एक और बैठक महाराष्ट्र में होगी। जिसमें चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अग्निवीर, पुरानी पेंशन योजना जैसे जन सरोकार के मुद्दों पर केन्द्र के खिलाफ सामूहिक आंदोलन तय हो सकते हैं जो पहले इंडिया का न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेंगे एवं आने वाले समय में उसके संयुक्त चुनावी घोषणापत्र के विभिन्न विषय भी। विपक्ष की इस सामने दिख रही आंधी को रोकने के लिये भाजपा ने न केवल एनडीए को पुनर्जाग्रत किया है वरन ऐसे–ऐसे दलों को भी अपने खेमे से जोड़ा है जो या तो अल्प ज्ञात हैं अथवा जिनके बारे में ज्यादातर ने पहले कभी सुना भी नहीं था। उससे नये जुड़े कुछ दल ऐसे हैं जिनका न कोई विधायक है और न सांसद। कुछ दलों की विधायिकाओं में बेहद क्षीण उपस्थिति है। पिछले दो लोकसभा चुनावों के भाजपा के अनेक सहयोगी पार्टियां एनडीए से कुछ समय पहले पल्ला झाड़ चुकी थी, उन्हें भी बुलाया गया है। कुछ तो वे दल हैं जिनके नेताओं के साथ भाजपा के कटु सम्बन्ध रहे हैं। अपमान का घूंट सहकर भाजपा इन्हें अपनी बगल में बैठाने पर मजबूर है। यह सत्तारुढ़ दल की बेचैनी और घबराहट का ही परिचायक है क्योंकि मोदी ब्रांड पर पूर्णतरू आश्रित एनडीए को जमीनी हकीकत का एहसास होते ही इल्मध हुआ कि अकेले दम उसके लिये अगला चुनाव जीतना सम्भव नहीं है। जहां एनडीए का खेमा परिस्थितिजन्य व स्वार्थपरक गठजोड़ है वहीं पहले यूपीए और अब इंडिया लोकतंत्र को बचाने के व्यापक प्रयोजन और जनहित के लिये बना स्वस्फूर्त गठबन्धन है। यह भी अंतर स्पष्ट है कि एनडीए को मजबूत बनाने के लिये भाजपा छोटे–छोटे दलों के पास जा रही है जबकि इंडिया से जुड़ने स्वयं बड़ी पार्टियां आ रही हैं। इनमें वे दल भी हैं जो कभी कांग्रेस को गरियाते थे या उसे कमजोर मानकर खारिज करते रहे हैं। इंडिया और एनडीए के शिविरों का बड़ा फर्क यही है कि इंडिया में ज्यादातर ऐसे दल व नेता हैं जिनकी अपने–अपने राज्यों में मजबूत स्थिति है। कई ने भाजपा को अपने राज्यों में हराया भी है या दूसरे क्रमांक पर हैं। आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्रियों और कई कद्दावर नेताओं की मौजूदगी के कारण इंडिया के प्रभाव को फीका करने के लिये भाजपा ने अपना पुराना खेल खेला है जिसे श्हेडलाइन मैनेजमेंट्य कहा जाता है। विपक्ष की पूर्व निर्धारित इस बैठक का (जो पहले शिमला में 12 जुलाई को होनी तय थी) जवाब देने के लिये आनन–फानन में मंगलवार की शाम को दिल्ली में भाजपा ने एनडीए की बैठक बुला ली। 2024 के चुनावों के मद्देनजर होने वाली इस सियासी हलचल की थाह लेने के लिये दोनों मोर्चों के स्वरूपों व प्रयोजनों को समझे बिना इसका सही विश्लेषण नहीं हो सकेगा और न ही मतदाता उपयुक्त फैसला ले सकेंगे।

आज का राशिफल

मेष :– योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। विरोधियों की प्रबलता से कार्य क्षेत्र में कठिनाईयाँ संभव।

बृषभ :– रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर उत्साह का संचार करेंगे, परन्तु आवेश में लिया गया निर्णय हानिकारक हो सकता है। जो बीत गयी उसे भूल वर्तमान में जीने की चेष्ठा करें।

मिथुन :– दूसरों की सफलता से अपने अन्दर हीन भावना ना पाले। नौकरी का वातावरण थोड़ा अरुचिकर और स्थान परिवर्तन के भी योग हैं। किसी सहकर्मी खराब व्यवहार से कष्ट संभव।

कर्क :– प्रयासरत कोई महत्वपूर्ण कार्य हल होने से मन प्रसन्न होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का भरपूर लाभ उठाने का समय आ गया है। किसी विपरीत लिंगी सम्बन्ध में आकर्षण बढ़ेगा।

सिंह :– नाजुक सम्बन्धों मे भावनात्मक ताल–मेल बिठाने का प्रयत्न करें। नये कायां के क्रियान्वयन के लिए प्रयत्न तीव। भावनात्मक अभिब्यक्ति सम्बन्धों मधुरता बढ़ेगी। कुछ नये उत्साह की अनुभूति करेंगे।

कन्या :– पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। दूसरों की आलोचना का अपने मनोबल पर असर न पड़ने दें। ग्रहों की अनुकूलता से प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे।

तुला :– कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुरूप चलने का प्रयत्न करें। शिक्षा–प्रतियोगिता के दिशा में परिश्रम तीव्र होगा। कुछ आर्थिक प्रगति के लिए मन में नई–नई युक्तियाँ उत्पन्न होंगी।

वृश्चिक :– आसीम प्रतिभाओं के बावजूद भी हीन मन प्रतिभाओं के लाभ से वन्चित होगा, अतरू इसे सुधारें। रोजगार की समस्याओं को लेकर मन चिन्तित होंगा। मन आपसी तालमेल बैठाने में असमर्थ होगा।

धनु :– दूसरों की बात इधर से उधर करना आपको शोभा नही देता। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होग। परिवारिक संबंधों में कटुता पैदा न होने दें। किसी बड़ी यात्रा के प्रति मन उत्साहित होगा।

मकर :– अपनी क्षमताओं व गुणवत्ता पर भरोसा रखें आगे बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। पुराने संबंधी से आकस्मिक भेंट संभव। रोजगार में सफलता के योग हैं। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में व्यय संभव।

कुंभ :– कल्पनाएं व आकांक्षाएं अपनी सार्थकता हेतु आपको उद्वेलित करेंगी। राजनैतिक सरगर्मियाँ आपकी व्यस्तता बढ़ाएंगी। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानी पैदा हो सकती हैं।

मीन :– कोई महत्वपूर्ण आकांक्षा अपनी सार्थकता हेतु आपको उद्वेलित करेंगी। अपकी सारी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। थोड़ धैर्य पूर्वक वक्त का इन्तजार करें। स्वास्य के प्रति सचेत रहें।

'इंडिया' बनाम 'एनडीए'

2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल अब बेंगलुरू में देश के 26 विपक्षी दलों के 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव एलांयस) अर्थात भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबन्धन की बैठक होने के जवाब में नई दिल्ली में 38 दलों के 'एनडीए' या राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक गठबन्धन की बैठक के साथ बज चुका है। 'एनडीए' भाजपा के नेतृत्व में केन्द्र में सत्तारूढ़ गठबन्धन कहलाता है जिसमें हाल ही में नये छोटे– छोटे दलों को शामिल करके इसकी संख्या 38 तक पहुंची है जबकि 'इंडिया' गठबन्धन में प्रमुख विपक्षी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के अलावा अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं। मगर इन दोनों गठबन्धनों के अलावा कुछ ऐसे और क्षेत्रीय दल भी हैं जो अपने– अपने राज्यों में सत्तारूढ़ होने के बावजूद किसी भी गठबन्धन में शामिल नहीं हुए हैं। इसमें आन्ध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस, ओडिशा की बीजू जनता दल व तेलंगाना की भारत राष्ट्रीय समिति प्रमुख हैं। इन तीनों दलों को इनका पिछला संसदीय रिकार्ड देखते हुए विपक्ष की राजनीति का हिस्सा नहीं माना जा सकता है क्योंकि संसद में इन दलों के सांसदों ने हमेशा आड़े वक्त पर मोदी सरकार का समर्थन करने को वरीयता दी है। अतः सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा ऐसे दलों को यदि 'सपक्ष' कहा जाये ये तो कुछ गलत नहीं होगा। ये दल अपने–अपने राज्यों में विधानसभा स्तर पर मजबूत जरूर हैं मगर 2024 की सीधी लड़ाई को देखते हुए इनके हाशिये पर रहने का जरूर अन्दाजा लगाया जा सकता है क्योंकि राजनीति के तेवर देखते हुए लोकसभा चुनाव के मुद्दे सीधे भारत की जनता के साझा मुद्दे ही हो सकते हैं। मगर हमें यह ध्यान रखना होगा कि लड़ाई बेशक 'इंडिया' गठबंधन व 'एनडीए' के बीच ही दिखाई जाये मगर असली मुकाबला अन्ततः कांग्रेस पार्टी व भाजपा के बीच ही होगा क्योंकि दोनों गठबन्धनों में केवल ये दो पार्टियां ही हैं जिन्हें विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय पार्टी कहा जा सकता है। मगर इन दोनों पार्टियों के साथ एक विडम्बना यह है कि जहां भाजपा विन्ध्याचल पर्वत के पार दक्षिणी भारत में बहुत कमजोर है वहीं कांग्रेस उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हाशिये पर खिसक चुकी है।

उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं जबकि दक्षिण भारत के पांच प्रमुख राज्यों कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल व तमिलनाडु में लगभग सवा सौ सीटें हैं। अतः 2024 की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है मगर एक बात तय है कि राजनैतिक दलों द्वारा इन चुनावों के प्रचार में सार्वजनिक बयानों के स्तर को चाहे जितना भी नीचे गिराया जाये परन्तु सार्वजनिक जन विमर्श अन्ततः सैद्धान्तिक मुद्दों पर ही बने रहने की उम्मीद है क्योंकि विपक्षी गठबन्धन ने जिस तरह अपना नाम इस देश के 'अंग्रेजी' नाम इंडिया पर रखा है उससे आम मतदाता की राजनीतिज्ञों से ऊंचा व्यवहार व आचरण करने की अपेक्षाएं बढ़ जायेंगी। मैंने कल ही लिखा था कि 2024 के चुनाव साधारण लोकसभा चुनाव नहीं होंगे और अगली पीढिघ्यों की किस्मत तय करने वाले होंगे तथा बदलते वैश्विक घटनाक्रम में भारत की दशा तय करने वाले होंगे। अतः सत्तारूढ़ गठबन्धन ने भी आज प्रधानमन्त्री नेतृत्व में अपनी बैठक करके साफ कर दिया है कि उसके निशाने पर विपक्षी गठबन्धन का विमर्श ही रहेगा जिससे वह अपना विमर्श जनता में लोकप्रिय बना सके परन्तु लोकतन्त्र में असल विमर्श वही होता है जिसे आम जनता स्वीकार करती है क्योंकि वही लोकतन्त्र की असली मालिक होती है और देश के संविधान पर उसे पूरा भरोसा होता है और वह मानती है कि भारत में जो भी होगा वह संविधान की कसौटी पर खरा उतरने वाला ही होगा। अतः विपक्षी गठबन्धन इन चुनावों में संविधान का मुद्दा जिस तरह उठा रहा है और लोक कल्याणकारी राज की आवाजें जिस तरह जनता के बीच ही गूंज रही हैं, वह भी देखने वाली बात होगी। इस सम्बन्ध में हमें सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि भारत के संविधान को भारत के लोगों ने ही अपने ऊपर लागू करने की 26 जनवरी, 1950 को कसम खाई थी जिसमें सामाजिक असमनता से आर्थिक विषमता दूर करने के लिए सरकारों को विशेषाधिकार दिये गये थे और प्रत्येक व्यक्ति के निजी सम्मान व गौरव की गारंटी दी गई थी। चुनावों के माध्यम से हर पांच वर्ष बाद देश की जनता अपने इन्हीं अधिकारों को पुनर्स्थापित करती है और ऐलान करती है कि भारत ऐसा देश है जिसमें आम आदमी की सत्ता में सीधी भागीदारी उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। इसीलिए लोकतन्त्र में संसद में बहुमत के आधार पर चुनी गई विशेष राजनैतिक दल की सरकार शपथ लेते ही हर उस मतदाता की सरकार भी हो जाती है जिसने बहुमत वाले राजनैतिक दल के खिलाफ चुनावों में वोट दिया होता है। यही वजह कि अल्पमत में रहने वाले विपक्षी दलों की संसद के माध्यम से सत्ता में भागीदारी करने की व्यवस्था हमारी संसदीय प्रणाली में है। संसद में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच गरमागरम या जोरदार बहसें अकारण ही नहीं होती बल्कि उनसे तय होता है कि सत्ता पक्ष में बैठे दल की नीतियों में जरूरत पड़ने पर जनता के हित में संशोधन किया जा सके। इसीलिए लोकतन्त्र को लोकसंवाद की प्रणाली भी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली को स्थापित करने वाले हमारे दूरदृष्टा पुरखे हमें यही समझा कर गये हैं कि लोकतन्त्र में गठित सरकार मालिक जनता की सेवा करने के लिए होती है जिसे हर पांच साल बाद जनता ही उसे उसकी मेहनत का मेहनताना देती है। अतः सभी राजनैतिक दलों की पुरजोर कोशिश होनी चाहिए कि चुनावी जन–विमर्श केवल आरोप–प्रत्यारोप का प्रदर्शन होकर न रह जाये बल्कि संसद से लेकर सड़क तक सार्थक विषयों का पुलिन्दा हो।

आरबीआई का आकलन

आदित्य नारायण

खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ौतरी के कारण जून में खुदरा मुद्रा स्फीति में आई तेजी यह दर्शाती है कि मुद्रा स्फीति के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इस समय टमाटर समेत फल–सब्जियों की कीमतों में बढ़ौतरी आम आदमी की चिंता का सबब बनी हुई है। मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ौतरी के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पांच महीने में पहली बार जून में बढ़कर 4.81 प्रतिशत हो गया, जो मई में 4.31 प्रतिशत था। हालांकि यह आरबीआई के सहनशीलता बैंड के भीतर है। अप्रैल में मुद्रा स्फीति की दर 4.7 प्रतिशत थी। आरबीआई का आंकलन स्पष्ट है कि महंगाई के मोर्चे पर अभी जंग जारी है। सब्जियों के दामों में महंगाई यद्यपि मौसमी और बाढ़ प्रभावित इलाकों से आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने के कारण है लेकिन अन्य खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से जनजीवन प्रभावित है। वैसे तो दुनिया के बड़े–बड़े देश महंगाई पर काबू पाने के लिए जूझ रहे हैं। महंगाई का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, लेकिन यह संतोष का विषय है कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम.घ्पात्रा और अन्य आरबीआई के अधिकारियों ने मुद्रा स्फीति को लेकर अपना आंकलन प्रस्तुत किया। मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच आरबीआई ने मुद्रा स्फीति पर लगाम लगाने के लिए रेपो दर में बढ़ौतरी की थी, जिस पर आरबीआई बैंकों कोघ्उनकी अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार देता है। अप्रैल और जून की मौद्रिक नीतियों में आरबीआई ने रेपो दर को अप्रवर्तित छोड़ दिया था। उसके बाद मुद्रा स्फीति की दरों में नरमी देखी गई थी लेकिन भारत में मानसून की वर्षा ने काफी गड़बड़ कर दी है। इससे पहले पिछले माह आई आरबीआई रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मुद्रा स्फीति अधिक रहने से निजी खपत पर होने वाले खर्च में कमी आ रही है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनियों की बिक्री में सुस्ती और क्षमता निर्माण मेंघ निजी निवेश में गिरावट आ रही है। जब तक मुद्रा स्फीति नीचे नहीं आती तब तक इससे जुड़ी उम्मीदों को स्थिर करने और उपभोक्ता व्यय बहाल करने में मदद नहीं मिलेगी। कम्पनियों की बिक्री तभी बढ़ेगी जब

लोग पैसा खर्चेंगे। भारत इस मामले में भाग्यशाली है कि उसकी अर्थव्यवस्था के सभी संकेत काफी बेहतर हैं। भारत की विकास दर तेजी से बढ़ रही है और वह दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने ही कहा था कि मुद्रा स्फीति को निर्धारित सीमा के भीतर लाने का काम अभी आधा ही हुआ है। इसलिए मुद्रा स्फीति वृद्धि परिदृश्य का आंकलन करने की जरूरत है। आरबीआई ने घवित्त वर्ष 23–24 के लिए देश की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। जैसे–जैसे व्यापक आर्थिक सम्भावनाएं लगातार बेहतर हो रही हैं। भारत अपनी पूरी क्षमता को गतिशील बना रहा है। केन्द्र की मोदी सरकार भी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। पूरा यूरोप महंगाई से परेशान है। रूस–यूक्रेन युद्ध के चलते भी वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न पदार्थों और ऊर्जा की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। यही कारण है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपनी ब्याज दरों में लगातार बढ़ौतरी करते जा रहे हैं। महंगाई के चलते आम आदमी की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस समय उड़द और अरहर जैसी दालें भी काफी महंगी हो चुकी हैं। दूध की कीमतों में लगातार बढ़ौतरी हो रही है। यही कारण कि केन्द्र सरकार ने 2 जून को अरहर और उड़द के स्टॉक की जमाखोरी करने पर रोक लगा दी थी। महंगाई नागरिकों के लिए अभिशाप स्वरूप है। हमारा देश एक गरीब देश है। यहां की अधिकांश जनसंख्या के आय के साधन सीमित हैं। इस कारण साधारण नागरिक और कमजोर वर्ग के व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। बेरोजगारी इस कठिनाई को और भी अधिक जटिल बना देती है। व्यापारी अपनी वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं। इसके कारण वस्तुओं के मूल्यों में अनियन्त्रित वृद्धि हो जाती है, परिणामतः कम आय वाले व्यक्ति बहुत–सी वस्तुओं और सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। महंगाई के बढ़ने से कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को अपने गोदामों में छिपा देते हैं। आजकल रोजमर्रा की वस्तुओं की कालाबाजारी हो रही है। रूस से सस्ता तेल और गैस मिलने के कारण भारत को कोई बड़े संकट का सामना नहीं करना पड़ा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल होते ही कृषि उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। रूस द्वारा यूक्रेन से अनाज निर्यात समझौता तोड़ देने से विश्व भर में गेहूं की कीमतों में उछाल आएगा लेकिन इसका भारत पर कोई ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि भारत के खाद्यान्न भंडार पर्याप्त हैं और वह कई देशों को अनाज निर्यात भी करता है।

तिब्बत पर भारत भी अपनी चुप्पी तोड़े

दुनिया के किसी भी मंच पर तिब्बत या दलाई लामा का नाम आते ही चीन की सरकार और उसके नेता आपा खोने लगते हैं। चीनियों की इस बौखलाहट से वही सच्चाई बेनकाब होती है कि तिब्बत को लेकर उसके मन में बहुत बड़ा चोर बैठा है। इस कारण चीनी सरकार किसी अपराधबोध के तले खुद को नैतिकता के धरातल पर बहुत असहाय पाती है। इसका एक उदाहरण हाल में देखने को मिला। भारत यात्रा पर आईं अमेरिकी अवर सचिव और तिब्बती मामलों पर अमेरिकी सरकार की विशेष प्रतिनिधि उजरा जेया और भारत में अमेरिकी राजदूत की दलाई लामा के साथ भेंट पर चीन सरकार ने जैसी तल्ख एवं आक्रामक टिप्पणी की, वह इस सामान्य घटना के अनुपात में बहुत असामान्य और चौंकाने वाली थी। चीनी दूतावास ने इस भेंट पर त्वरित प्रतिक्रिया में इसे अमेरिकी प्रतिनिधि की एक चीन विरोधी 'आक्रामक कार्रवाई' और अमेरिका द्वारा चीन के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बताया। चीनी प्रवक्ता ने अमेरिकी सरकार को लगभग धमकाते हुए अंदाज में कहा कि अमेरिका अपने इस आश्वासन का सम्मान करे कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और उसे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की हरकतें बंद करके चीन विरोधी अलगाववादी शक्तियों को समर्थन देना बंद करना चाहिए। चीन की इस आक्रामक प्रतिक्रिया का एक और रोचक पहलू यह रहा कि इस बार चीनी दूतावास ने अपने बयान में 'तिब्बत' के बजाय उसके लिए चीनी नाम 'शीजांग' का उपयोग किया। यह चीन सरकार की उस नई रणनीति को दर्शाता है जिसके तहत चीन अंतरराष्ट्रीय विमर्श से 'तिब्बत' शब्द के अस्तित्व को ही खत्म करने पर आमादा है। अब तिब्बत पर चीन की सरकारी प्रतिक्रियाओं में 'तिब्बत' के बजाय चीनी नाम 'शीजांग' का इस्तेमाल ठीक उसी प्रकार किया जाने लगा है, जैसा चीन ने 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जा जमाने के बाद उसके लिए चीनी नाम शिनजियांग का इस्तेमाल करके किया था। चीन की उस नीति का परिणाम यह हुआ कि धीरे–धीरे विश्व समुदाय यह भूल चुका है कि 1949 से पहले पूर्वी तुर्किस्तान एक स्वतंत्र देश था, जिस पर माओ की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने जबरन कब्जा कर लिया था। इसके एक साल बाद ही चीन ने विश्व समुदाय के देखते–देखते एक स्वतंत्र पड़ोसी देश तिब्बत पर भी कब्जा जमा लिया था। उजरा जेया और दलाई लामा की ताजा भेंट पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया को अगर पिछले कुछ वर्षों की अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो मामला समझना आसान हो जाता है। चीन के रास्ते अरबों डालर कमाने को लालायित अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और चीन समर्थक लाबी गुटों के दबाव में आकर पिछली कई अमेरिकी सरकारें अपने तिब्बत–प्रेम को भुलाकर बीजिंग की मिजाजपुर्सी वाले बयान देती रहीं। इस बीच पश्चिमी पूंजी और व्यापार के बूते चीन के आर्थिक एवं सामरिक रूप से ताकतवर होने के बाद अमेरिका–चीन 'हनीमून' समाप्त होने पर अब अमेरिकी सरकारों को चीन के मुकाबले अपनी कमजोरी का अहसास होने लगा है। लिहाजा, अब अमेरिका की नई रणनीति चीन की ऐसी हर कमजोरी को अपने हित में साधने पर टिकी है जिसका इस्तेमाल करके वह चीन के मुकाबले अपना अंतरराष्ट्रीय वर्चस्व कायम रख सके। चीनी आक्रामकता से पीड़ित भारत, ताइवान, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ नए सामरिक और आर्थिक गठजोड़ बनाने की अमेरिकी पहल भी इसी रणनीति का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर और आसियान देशों में चीनी आतंक ने भी भारत जैसे देशों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न की है। अपनी नई रणनीति के तहत अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में तिब्बत और पूर्वी–तुर्किस्तान पर कुछ नए कानून बनाए हैं, जिनके तहत वह चीन के औपनिवेशिक कब्जे में फंसे इन देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय माहौल बनाने में जुटा हुआ है।

इनमें से एक कानून में अगले दलाई लामा के अवतार की नियुक्ति के सवाल पर चीन सरकार को सीधी चुनौती दी गई है तो अमेरिकी संसद में तिब्बत को एक 'कब्जाया हुआ देश' बताने संबंधी विधायी प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया। ऐसे ही दो कानून शिनजियांग के समर्थन में बनाए जा चुके हैं। उजरा जेया को तिब्बत संबंधी मामलों की विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने से पहले पिछली अमेरिकी सरकारें इसी पद पर राबर्ट डेस्ट्रो और कोंडोलीजा राइस जैसे दिग्गजों को नियुक्त कर चुकी हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष टालने की मुहिमं

गंगा–जमुना का मायका उत्तराखंड आजादी के बाद से ही सामाजिक आंदोलनों के जरिये रचनात्मक बदलाव के लिये जाना जाता है। इसी धरती से ही गौरा देवी द्वारा शुरू किया गया चिपको आंदोलन आज भी पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक माना जाता है, जिसमें महिलाओं ने पेड़ों से जुड़कर पेड़ों के कटान को रोका था। इसी तरह बेटी के कन्यादान के समय वृक्ष लगाने का मैती आंदोलन भी खासा चर्चा में रहा। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की अस्मिता को लेकर चलाये गये आंदोलन में मसूरी, खटीमा व रामपुर तिराहा कांड में महिला आंदोलनकारियों की शहादत इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उत्तराखंड के बारे में कहावत है कि 'पहाड़ की जवानी व पानी पहाड़ के काम नहीं आते।' उत्तराखंड की आबादी के बराबर आबादी का प्रवासित होना इसकी बानगी दर्शाता है। हजारों गांव आज खाली हो गये हैं, जिनमें अब जंगली जानवरों का वर्चस्व है। जो उत्तराखंड की खेती व फल उत्पादन के लिये नासूर बन चुके हैं। खासकर बंदरों , जंगली सूअरों व तेंदुओं की बढ़ती अप्रत्याशित आबादी से ग्रामीण जन–जीवन बुरी तरह त्रस्त है। वे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस संकट के समाधान और वन्य जीवों को जंगल तक सीमित करने के मकसद से नया रचनात्मक आंदोलन उभरा है 'बीज बम' अभियान। जिसका मकसद है कि जंगलों में उत्तराखंड में उगने वाली सब्जियों व फलों को कुदरत के सान्निध्य में उगाया जाये ताकि जंगली जानवर, बंदर व अन्य जीवों को खाने के लिये जंगल के भीतर ही सब्जी–फल मिल सकें। जिससे वे मानव बस्तियों में उत्पात मचाने न आ सकें। खासकर उत्तराखंड में बंदरों के उत्पात से लोगों को राहत मिल सके। दरअसल, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में द्वारिका प्रसाद सेमवाल द्वारा कुछ साथियों व छात्रों की मदद से शुरू किये गये 'बीज बम' अभियान को जनता का आशातीत प्रतिसाद मिल रहा है। यह अभियान उत्तराखंड की साढ़े तीन सौ ग्राम पंचायतों व करीब ढाई सौ स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों के सहयोग से सिरे चढ़ रहा है। जो इस आंदोलन की सार्थकता और स्वीकार्यता का पर्याय ही है।

यह सुखद ही है कि 'बीज बम' आंदोलन केवल उत्तराखंड में ही जंगल में मंगल नहीं कर रहा है बल्कि देश के 18 राज्यों व चार दूसरे देशों में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। इस आंदोलन की सार्थकता का पता इस बात से चलता है कि जुलाई माह में चलने वाले एक सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान दो लाख से अधिक बीज बम जंगलों में डाले गये हैं। इन बीज बमों में स्थानीय सब्जियों–फलों के बीज शामिल हैं। कद्दू, तोरी, मक्का व शहतूत आदि के बीजों को उगाने के मकसद से बिखेरा गया है। इस आंदोलन का एक आधार स्तंभ हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान यानी जाड़ी है, जो अभियान को बीज उपलब्ध कराने में सहायक है। इस आंदोलन की सफलता का पता इस बात से चलता है कि इस बार बीज बम सप्ताह के दौरान नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका व दक्षिण अफ्रीका के कुछ संगठनों ने भागीदारी की। इतना ही नहीं, अब आंदोलन साल में एक बार मनाये जाने वाले बीज बम सप्ताह की सीमाओं से निकलकर वर्षपर्यंत चलने वाला कार्यक्रम बन चुका है। विभिन्न संगठनों, विभागों तथा शिक्षण संस्थानों के लोग वर्षपर्यंत अपनी सुविधा से बीज बम तैयार करके जंगलों में डाल रहे हैं। इस अभियान को जनता का सकारात्मक प्रतिसाद तो मिला ही है, सरकार भी इस पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को लेकर सकारात्मक रुख दिखा रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि इस रचनात्मक बीज बम आंदोलन को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

निस्संदेह, पर्यावरण संरक्षण और वन संपदा की रक्षा के लिये सरकारी कार्यक्रमों के बजाय जनांदोलन महत्वपूर्ण व ठोस भूमिका निभाते हैं। ऐसे स्वतरूस्फूर्त आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में बदलावकारी साबित हुए हैं। सरकार व विभिन्न पर्यावरण संगठनों का दायित्व है कि ऐसे रचनात्मक आंदोलन का वित्तीय पोषण करें ताकि स्वयंसेवी संगठनों का उत्साह बना रहे। ग्लोबल वार्मिंग संकट के इस दौर में पर्यावरण संरक्षण के जनांदोलन को प्रोत्साहित करना वक्त की जरूरत भी है।

वृक्ष जीवन प्रदाता हैं बिना वृक्ष के जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती है : डॉ हरि ओम

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के तहत आज तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के समाजशास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेवा योजना की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ. माया सिंह एवम समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. हरिओम त्रिपाठी के संयोजकत्व में बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 22 जुलाई को राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा पोषित गांव कुद्धुपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए चर्चा हुई, राष्ट्रीय सेवा योजना की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी माया सिंह ने शासन द्वारा निर्धारित स्लोगन ष्पर्यावरण रक्षा कर पाओ जीवन का अमरदान, पर्यावरण है हमें प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान।ष पर चर्चा करते हुए, वृक्षारोपण कार्यक्रम पर प्रकाश डाला, डॉ. हरिओम त्रिपाठी ने कहा की वृक्ष जीवन प्रदाता हैं, वेगैर वृक्ष के जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती है, कार्यक्रम में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर शिक्षक संघ के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विपिन सिंह, डॉ. शैलेंद्र सिंह वत्स, डॉ. जीतेश सिंह, कुद्धूपुर के ग्राम प्रधान एवम कर्मचारी विक्की सिंह आदि लोग उपस्थित रहें।

4306 के सापेक्ष 3806 आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी व सहायिका स्थापना की तैनाती

शीघ्र ही होगी रिक्त पदों पर भर्ती - अजय कुमार त्रिपाठी

अयोध्या।जिले के सभी विकास खण्डों में आंगनबाड़ी कार्यकत्री,मिनी कार्यकत्री व सहायिका कार्यकत्री के कुल 4306 पद स्वीकृत हैं।जबकि इसके सापेक्ष कुल 3806 पद भरे हुए हैं और अभी भी लगभग 500 पद

आंगनबाड़ी कार्यकत्री,मिनी कार्यकत्री व सहायिका कार्यकत्री के खाली पड़े हुए हैं। बताते चलें कि कि इस समय जिले के अमानीगंज, बीकापुर, मसौधा, तारुन, हरिंगटनगंज,मवई,मया बाजार, पूरा बाजार, मिल्कीपुर, रुदौली, सोहावल व नगर क्षेत्र में कुल 1925 आंगनबाड़ी कार्यकत्री के सापेक्ष कुल 1713 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की तैनाती है। जबकि 212 आंगनबाड़ी कार्यकत्री की तैनाती अभी होनी है।इसी तरह मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री की तैनाती सभी विकास खण्डों पर 456 होनी थी जिसके सापेक्ष कुल 431 मिनी कार्यकत्रियों की तैनाती हुई है जबकि इस पद पर भी 25 मिनी कार्यकत्रियों की तैनाती होनी

बाकी है।वही जिले के सभी विकास खण्डों पर कुल 1925 सहायिका के रुप में तैनाती होनी थी। जबकि इसके सापेक्ष कुल 1662 पदो पर ही सहायिका स्थापना की तैनाती हुई है वहीं अभी भी इस पद पर कुल 263 सहायिका स्थापना की तैनाती होनी है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वास्तव में इस समय आंगनबाड़ी कार्यकत्री,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका स्थापना के पद पर कुछ पद खाली है।जिसे शीघ्र ही पूरा करा लिया जाएगा।उन्होंने बताया कि इसके लिये विभाग में कार्यरत कर्मियों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में शासन के मंशानुरूप कार्य करना उनकी प्राथमिकता है।शासन द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ सीधे बिना बिचौलिए व देरी के पात्रों को मिले।उन्होंने बताया कि हमारा यही प्रयास है हम समाज में रहने वाले कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ आंगनबाड़ी कार्यकत्री,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायक स्थापना के माध्यम से दिलाने का कार्य करे।उन्होंने बताया कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी उनकी प्राथमिकता में से एक है।

आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में भूजल सप्ताह आयोजित

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, लखनऊ में ष्भूजल सप्ताहष के अंतर्गत प्रधानाचार्या डा. ममता किरण राव के मार्गदर्शन में छात्राओं को भूजल दोहन के दुष्प्रभाव एवं वर्षा जल संचयन के महत्त्व के बारे में बताया गया एवं पेंटिंग प्रतियोगिता संपन्न कराई गयी। इस प्रतियोगिता में अलिजा, अनु राजपूत एवं जोया इरफान को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्या डा. ममता किरण राव ने भूजल के महत्त्व एवं इसके संरक्षण से संबंधित उपायों से छात्राओं को अवगत कराया। साथ – साथ में अपने घर – मोहल्लों को जल संरक्षण हेतु जागरुक करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक डा. दिनेश कुमार ने भूजल संरक्षण हेतु छात्राओं को प्रेरित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया।

2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा भारत

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास कर रहा है। इसको गति देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तैयार किया गया है जिसके माध्यम से हरित ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के साथ ही एनर्जी ट्रांजीशन की ओर बढ़ने के प्रयास किये जा रहे हैं।ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने योजना भवन में विश्वआर्थिक मंच के पदाधिकारियों, स्टेक होल्डर्स के साथ आयोजित गोलमेज सम्मेलन में यह बात कही। श्री शर्मा उत्तर प्रदेश में सेन्टर फॉर द फोर्थ इन्डस्ट्रीयल रिवोल्यूशन यानि सी4आईआर की स्थापना के लिए आयोजित सम्मेलन में विश्व आर्थिक मंच के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान कहा कि सभी को सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल विद्युत उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं फिर भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आग्रह है कि पश्चिमी देशों के कौशल, ज्ञान एवं तकनीकी प्रयोग को उपलब्ध कराने का भी प्रयास करें जिससे कि नवीकरणीय ऊर्जा को और सस्ता एवं सुलभ बनाया जा सके। उन्होंने इन्टरनेशनल सोलर एलाएंस की नई तकनीकी प्रयोग को सौर ऊर्जा में बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा उपभोग में देश का दूसरा बड़ा राज्य है। विगत वर्षों में 1.50 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। प्रदेश में 2030 तक 40 गीगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य है। विद्युत वितरण क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 56 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे। बुन्देलखण्ड में 4000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर बनाया जा रहा है। अतिरिक्त ऊर्जा से फरवरी 2028 तक में 22 गीगावाट एनर्जी पैदा की जा सकेगी। प्रदेश में एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में कार्य के लिए नई नीति बनायी जायेगी जिससे भविष्य में क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ को हासिल किया जा सके। प्रदेश सरकार का वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश में निवेश बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।सम्मेलन में राज्य मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा डॉ. सोमेन्द्र तोमर, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, प्रबंध निदेशक उत्पादन एवं पारेषण पी गुरूप्रसाद, इन्वेस्ट यूपी के एससीईओ प्रथमेश कुमार,रावर्टो वोका व देवमाल्या सेन, एनटीपीसी के ईडी प्रवीन सक्सेना सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत

संवाददाता

लखनऊ। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली एवं सृजन फाउंडेशन की सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान सजग के अंतर्गत स्कूल के बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मुंशीगंज, गोसाईगंज स्थित अमेठी पब्लिक इंटर कॉलेज में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ।

सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को किया गया जागरूक

रिपोर्ट –जनार्दन श्रीवास्तव

पाली–(हरदोई)। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) दयाशंकर ने बताया है कि शासन द्वारा 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी क्रम में आज जिला अस्पताल के आसपास अधोहस्ताक्षरी तथा यातायात निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से दो पहिया वाहन की हेलमेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित) सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरूद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की गई।

जनवरी 2024 में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर होटलों में बुकिंग की होड़

(डॉ अजय तिवारी जिला संबाददाता)

अयोध्या। जनवरी के तीसरे सप्ताह के लिए होटलों में लगी बुकिंग की होड़, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने वाले करा रहे होटल में एडवांस बुकिंग, बुकिंग कराने वालों में मीडिया संस्थान भी शामिल, अयोध्या में बढ़ते हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुरू किया है होम स्टे सेवा, अयोध्या में शुरू हो चुकी है पेइंग गेस्ट सेवा, मकर संक्रांति के पर्व पर प्रस्तावित है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह, प्रधानमंत्री करेंगे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत।

रोपी गई धान की फसल उखाड़ने पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज, सतीचौरा पुलिस चौकी इंचार्ज कर रहे मामले की विवेचना।

सोहावल–अयोध्या रौनाही थाना क्षेत्र की पिरखौली ग्राम पंचायत निवासी रनजीत सिंह अपने खेत में धान की रोपाई कराए थे गांव के निवासी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य धमसादीन रोपी गई बेरन को खुन्नस बस उखाड़ कर फेंक दिया बनी चौड़ी मेड को तोड़कर अपने खेत में मिल लिया। रणजीत सिंह ने बताया जिसका विरोध करने गए तो आरोपी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा । पीड़ित रंजीत सिंह ने बताया की आरोपी दबंग वह अपराधी प्रकृति का है मोहल्ले में अक्सर लोगों को दलित एक्ट में फंसाने की धमकी दिया करता है रंजीत सिंह का खेत आरोपी के बगल में होने के कारण अक्सर वह मेड काट लेता है तथा खुद थाने व तहसील मैं अक्सर पड़ोसियों की शिकायत किया करता है स उसकी फर्जी शिकायत से परेशान होकर अधिकारीगण लिख चुके हैं कि उक्त व्यक्ति शिकायत करने का आदी है स धान की फसल उखाड़ने तथा मारपीट करने की शिकायत रंजीत सिंह ने थाना प्रभारी रौनाही से पीड़ित ने की। जिस पर धमसा दीन वह उसके पुत्र के खिलाफ रोना ही थाने मैं रपट दर्ज कर ली गई है रौनाही थाना प्रभारी ओपी राय बताया मामले में आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

विधायक रामचंद्र यादव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर व चौकी सैदपुर का किया औचक निरीक्षण।

रुदौली–अयोध्या। विधायक रामचंद्र यादव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर में सास बेटा बहू मिलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर के चारों तरफ जलभराव दिखाई पड़ा।जिसको देखते हुए वह कार्यक्रम को संपन्न करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ का औचक निरीक्षण किया।व खामियों के लिए अधिकारियों को आदेश दिया।उन्होंने कहा कि मां कामाख्या धाम नगर पंचायत में अब साफ सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।जिससे कहीं भी जलभराव ना हो उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर के डॉक्टर समशेर कुमार को आदेशित करते हुए कहा कि आप एक स्टीमेट बनाइए।जिससे बाउंड्री व साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके।औचक निरीक्षण करते हुए विधायक ने सैदपुर चौकी का भी निरीक्षण कियाजिसके चलते चौकी सैदपुर के चारों तरफ साफ सफाई कराने को आदेशित किया।व रहने खाने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात भी की। एवं सैदपुर चौकी में हो रहे निर्माणाधीन मंदिर के बारे में भी चर्चा की। इस मौके पर भाजप।

पेंशनर आज करेंगे जंतर–मंतर पर अनशन और सांसदों का घेराव

संवाददाता

लखनऊ। पिछले 7 वर्षो से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोत्तरी और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर देशभर में पेंशनरों के आन्दोलन की सरकार द्वारा अनदेखी किए जाने से आक्रोशित पेंशनर दिल्ली में अनशन करेंगें। ईपीएस–95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत केंद्रीय कार्यकारणी के पदाधिकारियों के साथ संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर–मंतर पर अनशन पर बैठेंगे।उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के पेंशनर बड़ी संख्या में अनशन स्थल पर पहुंचेंगे। देश के प्रमुख शहरों में भी पेंशनर अनशन करेंगें।

948 विरासत वृक्षों को संवारेगी योगी सरकार

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत प्रदेश के 948 विरासत वृक्षों को संवारेगी। 100 वर्ष से अधिक आयु के 28 प्रजाति के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। यह वृक्ष प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हैं। उत्तर प्रदेश में सभी जनपद में विलुप्त हो रहे बृक्ष प्रजातियों के संरक्षण को लेकर जागरूकता भी पैदा की जायेगी। वाराणसी में सर्वाधिक 99, प्रयागराज में 53, हरदोई में 37, गाजीपुर में 35 और उन्नाव में विभिन्न प्रजातियों के 34 विरासत वृक्ष हैं। योगी सरकार विलुप्त हो रही इन वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण व पौराणिक ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, धार्मिक परंपराओं व मान्यताओं से जुड़े हुए वृक्षों को संरक्षित कर जन सामान्य में इसके प्रति जागरूकता पैदा कर रही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा हेरीटेज वृक्षों के चयन व अभिलेखीकरण हेतु दिशा–निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने गैर वन क्षेत्र पर अवस्थित सौ वर्ष से अधिक आयु के 28 प्रजातियों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। इनमें अरु, अर्जुन, आम, इमली, कैम, करील. कुसुम, खिरनी, शमी, गम्हार, गूलर, छितवन, चिलबिल, जामुन, नीम, एडनसोनिया, पाकड़, पीपल, पीलू, बरगद, महुआ, महोगनी, मैसूर बरगद, शीशम, साल, सेमल, हल्दू व तुमाल शामिल हैं। इसमें बरगद प्रजाति के 363 व पीपल प्रजाति के 422 वृक्ष हैं। विरासत वृक्ष में आध्यात्मिक व स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े वृक्ष शामिल किए गए हैं। योगी सरकार यूपी के सभी 75 जिलों में विरासत वृक्षों को खोजकर इन्हें संरक्षित करने को प्रतिबद्ध है। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में हनुमान मंदिर, काली मंदिर के समीप व गौशाला के अंदर बरगद व पाकड़ वृक्षों सहित पूरे जनपद में 19 वृक्ष विरासत वृक्ष घोषित किए गए हैं। वहीं लखनऊ व वाराणसी के क्रमशः दशहरी आम व लंगड़ा आम के मातृ वृक्ष, फतेहपुर का बाचन इमली, मथुरा के इमलीतला मन्दिर परिसर का इमली वृक्ष, प्रतापगढ़ का करील वृक्ष,बाबा झारखंड के नाम से प्रसिद्ध अम्बेडकर नगर का पीपल वृक्ष एवं आर्डिनेंस क्लॉथ फैक्ट्री शाहजहांपुर में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा पीपल वृक्ष शामिल है।

पीयू की प्रवेश परीक्षाएं 25 और 26 जुलाई को

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विषयों में सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा 25 और 26 जुलाई को आयोजित होगी। प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड 20 जुलाई को विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। 25 जुलाई को डिप्लोमा इन फार्मेसी, बीसीए, एमबीए, एमबीए (बिजनेस एकोनामिक), एमबीए (फाइनेंस कंट्रोल), एमबीए (ई–कामर्स), (एमबीए एग्रीबिजनेस), एमबीए (एचआरडी), बीकाम (आनर्स) एवं 26 जुलाई को बीएससी (जूलाजी, बाटनी, केमिस्ट्री, इनवार्मेंटल साइंस, फिजिक्स, मैथस, केमिस्ट्री, जिओलाजी, माइक्रोबायलाजी) बीएससी (आनर्स) बायोटेक्नालाजी, बीएससी (आनर्स) पर्यावरण साइंस, बीए. एल.एल.बी. (आनर्स) पांच वर्षीय इंट्रिग्रेटेड कोर्स तथा एमसीए की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। जिन विषयों में सीट से कम आवेदन आएं हैं उसका प्रवेश काउंसिलिंग, मेरिट के आधार पर 20 जुलाई से शुरू हो गया है। सभी परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर के फार्मेसी संस्थान में कराई जाएंगी। प्रवेश परीक्षा की समय सारणी एवं विभागों के मोबाइल नंबर सहित समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

शोध केंद्र ,श्री लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय,गोंडा में जनपद के ओजस्वी, साहित्य भूषण साहित्यकार श्री शिवाकांत मिश्र विद्रोही जी का आगमन हुआ

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

गोण्डा। शोध केंद्र ,श्री लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय,गोंडा में जनपद के ओजस्वी, श्साहित्य भूषणश साहित्यकार श्री शिवाकांत मिश्र श्विद्रोहीश जी का आगमन घ्हुआ। आपके कई महत्वपूर्ण खंडकाव्य, काव्य संकलन व समय –समय पर अनेक लेख पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपने आज श्री नानकचंद श्इशरतश के महाकाव्य श्कामदेव– विजयश की टंकित प्रति शोध केंद्र को सौंप दिया है। यह महाकाव्य अपने कलेवर में विशिष्ट इसलिए है क्योंकि इससे पहले कामदेव पर कोई महाकाव्य नहीं लिखा जा सका था। श्री नानक जी ने इसे अपने कार्यकाल में ही अपने शिष्य प्रेमचंद श्रीवास्तव जी को दिया था। जो जी. आइ. सी. गोण्डा में प्रवक्ता थे। 1985 में लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रहे शैलेंद्र मिश्र को भी इस कृति को प्रेमचंद श्रीवास्तव जी ने गोंडा के साहित्य सर्वे के दौरान पढ़ने के लिए दिया था। तदुपरांत प्रेमचंद जी ने श्विद्रोहीश जी को इसे प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी के साथ सौंप दिया था। लगातार शोध केंद्र के आग्रह पर उन्होंने यह कृति शोध केंद्र को भेंट की है। अब शोध केंद्र इसके संपादन ,प्रकाशन की व्यवस्था करेगा तथा हिंदी के विद्यार्थी इस पर घ्शोधा कार्य करेंगे।

शोध केंद्र राष्ट्रीय स्तर के चर्चित एवं प्रशंसित साहित्यकार श्री शिवाकांत मिश्रा श्विद्रोहीश के आभार व्यक्त करता है। महाविद्यालय का हिंदी विभाग आदरणीय श्री मिश्र जी के ऊपर शोध कार्य करा रहा है।

विद्युत उपकेंद्रों पर लगवाए जाये सीसीटीवी कैमरे

अधीक्षण अभियंता से मिला अपना व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल

संवाददाता

लखनऊ। विद्युत उपकेन्द्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा बिजली कनेक्शन जारी करने मे हीलाहवाली को लेकर अपना व्यापार मंडल के प्रतिनिधमंडल ने एसई से शिकायत की है। अधीक्षण अभियंता सर्किल 4 लेसा इं.राम प्रीत प्रसाद से प्रतिनिधिमंडल भेंट कर अपनी मांग रखी। उत्तर प्रदेश अपना व्यापार मंडल के प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव की अगुवाई मे आज तीन सदस्यीय प्रतिनिथिमंडल ने अधीक्षण अभियंता से मांग की कि विद्युत उपकेन्द्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाएं तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए।सेस –2 डिवीजन के अन्तर्गत दुबग्गा उपकेन्द्र के सिकरोरी के कई आवेदकों के कनेक्शन ट्रान्सफार्मर ओवरलोड का हवाला देकर पेंडिंग में डाल दिये गए। उन लोगों ने घरेलू कनेक्शन के आवेदन किया था जबकि एक प्रतिष्ठान को 17 जुलाई को 4 किलोवाट वाणिज्यिक कनेक्शन निर्गत कर दिया गया है। इनके लिए ओवरलोड का नियम लागू नही होता है। वही मो.तारिक ने 14 मई 2022 को इस्टीमेट कास्ट सहित कनेक्शन फीस भी दुबग्गा उपकेंद्र के अन्तर्गत जमा कर दी परन्तु आज तक संयोजन नहीं किया गया बल्कि आवेदक के यहां बिल जरूर रुपये 2933 का भेज दिया गया। मजीदन ने घरेलू कनेक्शन के लिए दुबग्गा उपकेन्द्र से 15 मई को आवेदन किया। संयोजन नहीं किया गया।प्रवक्ता अजय यादव ने अधीक्षण अभियंता को बताया कि साजिद अली ने दुबग्गा उपकेंद्र के अन्तर्गत अस्थायी कनेक्शन के लिए 3 जून को आवेदन किया लेकिन आज तक विभाग द्वारा उन्हें भी अस्थायी कनेक्शन नही मिला। सलमान अली ने मार्च माह मे एक पोल का इस्टीमेट सहित कनेक्शन फीस जमा कर दी, आज तक न पोल लगा न परिसर पर मीटर। प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि उपभोक्ता को सही समय पर बिल मिले तथा कनेक्शन देने मे हीलाहवाली न की जाए। इस पर अधीक्षण अभियंता ई.राम प्रीत प्रसाद ने कहा कि समस्याओं का निराकरण कराने का पूरा प्रयास किया जायेगा। कनेक्शन न निर्गत करने के मामले मे अभियंता से जवाब तलब होगा प्रतिनिधि मंडल मे अजय यादव, अधिवक्ता अनुज सिह और हँसराज मौर्या शामिल थे।

आरडीएसएस योजना में तेजी लाने हेतु अध्यक्ष ने दिये कड़े निर्देश

संवाददाता

लखनऊ। उप्र पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम0 देवराज ने आज शक्ति भवन में आर0डी0एस0एस0 योजना में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुये उसमें तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में बहुत बेहतर सुधार होने है इसलिये इसको निर्धारित समय से पूर्ण करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य सुनिश्चित किये जाये। उन्होंने पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना (आर0डी0एस0एस0) के कार्यों में तेजी लाने के लिये आज अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। यह योजना वितरण कम्पनियॉ की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने पर लक्षित है। भारत सरकार के सहयोग से यू0पी0 की विद्युत व्यवस्था को और सृदृढ़ करने काकार्य इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। जिस पर 13632 करोड़ रूपये का व्यय का अनुमान है। इस योजना में 2024–25 तक 12 से 15 प्रतिशत तक वाणिज्यि कहानियों को कम करने का लक्ष्य तय किया गया। इस योजना के अन्तर्गत यूपी के सभी पॉचों डिस्काम को 29 पैकेज प्रदान किये गये है। सभी पॉचों डिस्काम में प्रोजेक्ट कार्यों की शुरूआत हो चुकी है।

इसके अन्तर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के आठ कलस्टर के लिये 3842.41 करोड़, मध्यांचल के लिये 3303.70 करोड़ रूपये, पश्चिमांचल के लिये 2764.33 करोड़ रूपये, दक्षिणांचल के लिये 3247.07 करोड़ रूपये तथा केस्को के लिये 474.73 करोड़ रूपये आवंटित किये गये है। अध्यक्ष ने आज पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल तथा केस्को में योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यो की वृहद समीक्षा की तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण हो इसके लिये लगातार मानीटरिंग की जाये। जवाहरपुर एवं ओबरा परियोजना के निर्माण में तेजी लाने हेतु आज निर्माण में लगी कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी अध्यक्ष ने शक्ति भवन में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोरियन कम्पनी दूशान एवं अन्य कम्पनी के प्रतिनिधियों से कार्य में विलम्ब के लिये गंभीर असन्तोश व्यक्त करते हुये कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण में हो रहे विलम्ब से प्रदेश की विद्युत उपलब्धता बढ़ाने में कठिनाई होती है। आगामी महीनों में गर्मी बढ़ेगी ऐसी स्थिति में विद्युत उपलब्धता बढ़ाने हेतु उत्पादन ईकाइयों का समय से उत्पादन शुरू करना आवश्यक है।

यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक को पीटने वाले दोनों सिपाही सस्पेंड

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ के बारा बिरवा चौराहे पर युवक को पीटने वाले दो सिपाहियों को डीसीपी पश्चिमी राहुल राज ने सस्पेंड कर दिया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद किसी की राहुल राज में पुलिसकर्मियों और पीड़ित के सामने बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज होने के बाद डीसीपी ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर पूरे मामले की जांच एडीसीपी को सौंपी है। डीसीपी राहुल राज ने बताया कि मानक नगर के बारा बिरवा स्थित दो पुलिसकर्मियों के द्वारा विनीत सिंह नाम के युवक की पिटाई की गई थी। इस मामले में जांच की गई और हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनमोल मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच एडीसीपी को सौंपी गई है। आईएएस की तैयारी कर रहे विनीत सिंह को पुलिस स्मैक तस्कर बताकर जेल भेज चुकी होती।

340 लाभार्थियों को विद्युत चालित चाक, पैडल चालित अगरबत्ती मशीन और टर्नवुड क्रॉफ्ट मशीनों का किया गया वितरण।

अयोध्या। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भानु प्रताप सिंह वर्मा ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार और अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह की उपस्थिति में 340 लाभार्थियों को विद्युत चालित चाक, पैडल चालित अगरबत्ती मशीन और टर्नवुड क्रॉफ्ट मशीनों का वितरण किया। ग्राम विकास योजना के अंतर्गत अयोध्या के ग्राम स्वावलंबी विद्यालय, रनीवा में केवीआईसी के राज्य कार्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित वितरण कार्यक्रम में लखनऊ और गोरखपुर मंडलीय कार्यालय के लाभार्थी शामिल हुए। वितरण कार्यक्रम में अयोध्या से महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और केवीआईसी के उत्तर क्षेत्र के सदस्य नागेंद्र रघुवंशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री, एमएसएमई, भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि भारत के कुल सकल घरेलू उत्पादोंमें एक तिहाई योगदान डैडम् सेक्टर का है जो देश के 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डैडम् सेक्टर शानदार काम कर रहा है। श्री वर्मा ने आगे कहा कि ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पिछले 9 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किया है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थी कारीगरों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से गांव–गांव तक रोजगार पहुंचाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग लगातार प्रयत्नशील है। उन्हीं के नेतृत्व में पिछले वित्त वर्ष में इतिहास रचते हुए खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों का कारोबार 1.34 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केवीआईसी द्वारा ग्रामोद्योग विकास योजना के अन्तर्गत भारतीय परम्परागत उद्योगों के कामगारों को टूल्स एवं मशीनरी का वितरण किया जा रहा है, जिससे परम्परागत उद्योगों के कामगारों की आय में वृद्धि से उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो। अभी तक पूरे देश में कुम्हारों को 25,000 से अधिक विद्युत चालित चाकों का वितरण किया जा चुका है, जिससे कुम्हारों की आय में तीन से चार गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से 20 हजार मधुमक्खी पालकों को भी 2 लाख से अधिक मधुमक्खी बॉक्स और बी–कलोनी का वितरण किया जा चुका है। मधुमक्खी पालन से किसानों की उपज में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए मा0 अध्यक्ष, केवीआईसी, श्री मनोज कुमार ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। हमें मेक इन इंडिया के साथ–साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकल टू ग्लोबल विजन साकार हो पाएगा। इस अवसर पर अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही ग्राम विकास योजनाओं की प्रशंसा की और कहा कि इन योजनाओं से जुड़कर हमारे परंपरागत कारीगर स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अयोध्या के माननीय महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी ने लोगों से अपील की कि वो खादी और ग्रामोद्योगी स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। वितरण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, जालौन, झांसी, मऊ और आजमगढ़ के 260 कुम्हारों को विद्युत चालित चाक और कानपुर देहात के 20 कामगारों को अगरबत्ती मशीन का वितरण किया गया। साथ ही लखमीपुर खीरी, संतकबीर नगर और आजमगढ़ के 60 कामगारों को टर्नवुड क्रॉफ्ट मशीनें प्रदान की गईं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार और के.वी. आई.सी के अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे।

जुलाई माह के अन्तिम सप्ताह तक भारतीय जनता पार्टी में जिलों में संगठनात्मक बदलाव होने के आसार

अयोध्या। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से भाजपा जल्द ही जिलों में सांगठनिक बदलाव करेगी। जिलों में संगठन की धार पैनी करने के लिए पार्टी लगभग 50 प्रतिशत सांगठनिक जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए विचार कर रही है। नए जिलाध्यक्षों की तैनाती हर हाल में इस महीने के आखिरी हफ्ते में होने की प्रबल संभावना है।

भाजपा की प्रदेश टीम 25 मार्च को घोषित हुई थी। इसके साथ ही सभी छह सांगठनिक क्षेत्रों के अध्यक्ष भी बदले गए थे। प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर बदलाव के बाद प्रदेश नेतृत्व अब जिलों में सांगठनिक ढांचा सुदृढ़ करने में जुटा है। इसी कड़ी में पार्टी ने सभी सांगठिनक जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। पर्यवेक्षकों को संबंधित जिलों में जाकर वहां सांगठनिक फेरबदल के बारे में गोपनीय रिपोर्ट और नए जिलाध्यक्ष की तैनाती के लिए दावेदारों के नामों का पैनल प्रदेश नेतृत्व को 15 जुलाई तक सौंपना था। भाजपा ने प्रदेश को 98 सांगठनिक जिलों में बांट रखा है। सूत्रों की माने तो

अब तक 90 प्रतिशत जिलों में भेजे गए पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बाकी पर्यवेक्षकों से भी जल्द रिपोर्ट और नामों का पैनल देने के लिए कहा गया है।

अब तक सौंपी जा चुकी रिपोर्ट और नामों के पैनल में से नए जिलाध्यक्ष का नाम छांटने के लिए विचार मंथन भी शुरू हो गया है। नए जिलाध्यक्ष के चयन के लिए प्रदेश नेतृत्व क्षेत्रीय अध्यक्ष के अलावा स्थानीय सांसद और विधायकों व पूर्व विधायक तथा पदाधिकारियों से भी रायशुमारी किया था। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 50 प्रतिशत सांगठनिक जिलों में जिलाध्यक्षों के बदले जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिला अयोध्या धाम के महत्व को देखते हुए बहुत से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष बनने हेतु गुणा गणित लगाने में लगे हैं। वर्तमान जिला अध्यक्ष संजीव सिंह व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और कयास यह लगाया जा रहा है कि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के मझे कार्यकर्ता है।इनका कार्यकाल जरूर पूर्ण हुआ है परंतु अभी एक बार और अध्यक्ष के पद पर इन्हें ही नियुक्त कर इन्हीं से काम लिया जाए तो पार्टी के हित के लिए सर्वोपरि होगा। यह दोनों अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा। परंतु कुछ कालनेमि लोग जिन्होंने वक्त वक्त पर पार्टी में ही रहकर पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवारों का खुलकर विरोध किया यहां तक की खुल्लम–खुल्ला विरोधी के साथ प्रचार भी किया। वे लोग भी नए अध्यक्ष के चुनाव में अपनी दखलअंदाजी कर रहे हैं। और अपने आप को सच्चा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बता रहे हैं। पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने कहा कि वर्तमान में जनपद अयोध्या धाम के वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारियों के अंतरूभावना में काफी दूरियां है सत्ता के मद में अहंकार से वशीभूत जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं देते उनके अपने निजी दलाल ही भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता को चूना लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की चर्चा एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की है जिसने डूब क्षेत्र बिना लेआउट पास कराए प्रतिबंधित क्षेत्र में गरीबों के हाथ जमीन का सौदा किया उसको बेच भी डाला बेचारे गरीबों की हालत खराब है विकास प्राधिकरण ने उन गरीबों के मकान पर तो बुलडोजर चला दिया और जो कुछ बचे हैं उन पर भी बुलडोजर चलने वाला ही है ऐसे दलाल प्रॉपर्टी डीलर कार्यकर्ता भी महानगर अध्यक्ष बनने की लाइन में है । अगर ऐसे दलाल पार्टी के अध्यक्ष बनने की लाइन में रहेंगे तो पार्टी का बेड़ा गर्ग होना निश्चित है। जानकारी तो यहां तक उड़ कर आ रही है कुछ लोगों ने जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष बनाने के लिए सौदा भी किया है वह सौदागर कौन है क्या पार्टी उसके झांसे में आएगी या नहीं यह तो पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद ही पता चलेगा। वैसे जनपद अयोध्याधाम में संजीव सिंह कर्मठ कार्यकर्ता हैं ।लेकिन अगर पार्टी उन्हें बदलना ही चाहती है तो कमला शंकर पाण्डेय,राघुवेन्द्र नारायण पाण्डेय, रोशन लाल त्यागी, रणबीर सिंह, अवधेश पांडे बादल, मनोज वर्मा, कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू,व इन्द्र भान सिंह में किसी को बनाया जाय तो सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेंगे। वही महानगर अध्यक्ष पद हेतु भी बहुत मारामारी है अब तक दर्जनों दावेदार समाने आये हैं । महानगर में अभिषेक मिश्र जैसा दमदार अध्यक्ष होना चाहिए अगर पुनः उनका इंस्टेन्शन हो जाता तो पार्टी के हित में होता लेकिन अगर पार्टी अध्यक्ष के पद में बदलाव लाना चाहती है तो पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, गिरीश पांडेय, डिपुल, दिवाकर सिंह, रिंकू श्रीवास्तव, विशाल सिंह बाबा, परमानंद मिश्रा तथा नाका नरेश अभय सिंह में से किसी को बनाया जाता तो पार्टी में गुटबाजी का जो माहौल है उसमें विराम लगता यह लोग पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होने के साथ गुटबाजी से दूरी बना कर रखते हैं।

शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से 25 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिया गया

न्यायालय के आदेश पर शाखा प्रबंधक सहित सात पर धोखाधड़ी का दर्ज हुआ केस

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

खरगपुर गोंडा। बैंक शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से चाचा के खाते से भतीजे ने 25 लाख रुपए धोखाधड़ी कर अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शाखा प्रबंधक व बैंक कर्मी सहित सात लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।मामला स्थानीय नगर पंचायत स्थित इंडियन बैंक की शाखा खरगूपुर का है। इटियाथोक थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अर्जुनपुर निवासिनी साफिया बेगम पत्नी मोहब्बत अली द्वारा न्यायालय के आदेश पर स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा है कि उसके माता का पहले ही देहांत हो चुका है

और कोई भाई भी नहीं है। केवल दो बहने हैं और वह भी शादीशुदा है।थाना खरगूपुर के ग्राम पंचायत रंजीत नगर में उसके पिता मतई के पास भूमि है।उनका बैंक खाता संख्या 27710496549 इंडियन बैंक की शाखा खरगूपुर में है। जिसमें माह नवंबर 2021 में 38 लाख रूपये जमा थे। इसकी जानकारी उसके चचेरे भाई इंताज अली व चाचा चिनकू को था। उक्त दोनों लोगों ने अपने गांव के ही असगर अली, अशोक कुमार शुक्ला,राम केवल तथा इंडियन बैंक खरगूपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक तथा एक अन्य बैंक कर्मी से मिलीभगत कर एक ही दिन में 15 नवंबर 2021 को उसके पिता के खाते से 25 लाख रुपए इंताजअली के खाते में ट्रांसफर करा लिया गया।पैसा ट्रांसफर के पांचवें दिन उसके पिता मतई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मौत के पश्चात आरोपियों ने उसके पिता के खाते से बाकी रुपए निकालने के नियत से ट्रांसफर वाउचर के माध्यम से दो बार एक एक रुपए खाते में डाला।लेकिन मृतक की बेटी ने पिता की मौत की सूचना उसी दिन बैंक में दे चुकी थी। इसलिए आरोपी बाकी रकम निकालने में असफल रहे। दर्ज कराए गए प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शाखा प्रबंधक व बैंक कर्मी सहित उक्त आरोपियों ने एक राय होकर साजिश करके धोखाधड़ी के तहत उसके पिता के खाते से रुपए ट्रांसफर करा लिये। इस संबंध में साफिया बेगम ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा कर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना किए जाने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन इंडियन बैंक शाखा प्रबंधक खरगूपुर व बैंक कर्मी के साथ ही इंताजअली,अशोक कुमार शुक्ला, चिनकू,असगर अली,राम केवल के विरुद्ध धोखाधड़ी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

सही कागजात लेकर ही सड़क पर निकले व्यावासिक वाहन चालक - एआरटीओ प्रशासन

निजी वाहनों के व्यवसायिक कार्य में पाये जाने पर आरटीओ कसेगा शिकंजा

अयोध्या। परिवहन विभाग अब उन वाहन स्वामियों पर शिकंजा कसने जा रहा है जो निजी उपयोग के लिए वाहनों का पंजीकरण तो परिवहन विभाग में आकर करा तो ले रहे है।परंतु उसका उपयोग निजी कार्य क्षेत्र में न करके व्यवसायिक क्षेत्रों में कर रहे हैं।जिसके चलते राजस्व की भारी क्षति हो रही है।यह बातें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आर पी सिंह ने बताई।उन्होंने बताया कि इस समय यह शिकायत मिल रही है कि शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों, स्कूलों, बिजली विभाग, विश्वविद्यालय सहित अन्य सरकारी व निजी संस्थानों में निजी कार्यों के उपयोग के लिए वाहन स्वामी आरटीओ विभाग में अपने–अपने वाहनों का पंजीकरण कराते हैं। परंतु उन वाहनों का उपयोग निजी कार्यों में न करके बल्कि व्यावसायिक कार्यों करते हुये दिखाई दे रहे हैं। जिसके चलते राजस्व की काफी क्षति पहुंच रही है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आर पी सिंह ने बताया कि इससे राज्य की सकल घरेलू आय भी कम हो रही है।उन्होंने ऐसे वाहन स्वामियों से अपील किया है कि जो आरटीओ में अपने वाहनों का निजी वाहनों में पंजीकरण कराया है वे शीघ्र ही अपने वाहनों का समस्त कागजात लेकर उस वाहन का पंजीकरण व्यवसायिक वाहन में करा लें। नहीं तो शीघ्र ही परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी उन पर नियंत्रण लगाने के लिये सभी मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलायेगे। उन्होंने ऐसे वाहन स्वामियों से कहा कि जो लोग अपने अपने वाहनों का पंजीकरण तो निजी उपयोग के कराये है परंतु उपयोग व्यवसायिक क्षेत्रों में कर रहे हैं वे सभी शीघ्र ही आरटीओ विभाग में आकर अपने अपने वाहनों का पंजीकरण व्यवसायिक रुप में करा ले।

उ0प्र0 के पेंशनरों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन किया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

नई दिल्ली। ईपीएस–95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिये दिल्ली के जंतर–मंतर पर आयोजित अनशन में लखनऊ सहित उ प्र के अनेक जिलों के पेंशनरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कई वर्षो से ईपीएस–95 न्यूनतम पेंशन 7500 रू महीना व डी ए और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर पूरे देश में संघर्षरत है, पक्ष विपक्ष के सभी सांसदों को अनेको बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई सार्थक परिणाम न निकलने से पेंशनरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संसद के वर्तमान सत्र में अपनी माँगे पूरी कराने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए देशभर के पेंशनरों ने दिल्ली में डेरा डाला है। उत्तर प्रदेश से सर्व श्री के एस तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ओम शंकर तिवारी राष्ट्रीय सचिव, सी बी सिंह कार्यकारी अध्यक्ष, राजीव भटनागर मुख्य समन्वयक के साथ अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में प्रदेश के पेंशनर बड़ी संख्या में अनशन पर बैठे और सांसदों के दिल्ली स्थित आवास पर जाकर मांगों को पूरा कराने के लिए दबाव बनाया। पेंशनरों ने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों को मॉनसून सत्र में पूरा नही किया गया तो देशभर में व्यापक रूप से आन्दोलन होगा और इसका प्रभाव आगामी चुनावों पर भी दिखेगा।

लखनऊ में प्रदेश महामंत्री राज शेखर नागर के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया गया और ज्ञापन सौंपा गया।

जिसमें प्रांतीय संगठन मंत्री पी के श्रीवास्तव मध्य जोन के अध्यक्ष आर एन द्विवेदी, सुभाष चौबे, मंडल सचिव अशोक बाजपेई , गीता वर्मा , सुनीता सोनकर, लक्ष्मी कुरील सहित अनेक पदाधिकारी शामिल थे।

अपने उद्यम का रजिस्ट्रेशन करायें और निःशुल्क बीमा योजना का लाभ उठायें-दुर्गेश कुमार

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार ने गुरुवार को सभी उद्यमियों से कहा है कि अपने उद्यम का रजिस्ट्रेशन ॖनकलंउतमहपेजपवद.हवअ.पद पोर्टल पर करायें और निःशुल्क दुर्घटना बीमा का लाभ उठायें और जनपद में निःशुल्क बीमा के लिए 19103 उद्यम के रजिस्ट्रेशन हो चुके है।

उन्होने जनपद के समस्त औद्योगिक, वाणिज्यिक, सेवा प्रदाता इकाईयों, प्रतिष्ठान जैसे विनिर्माण एवं सर्विस क्षेत्रान्तर्गत आने वाली इकाईयों के उद्यमी, व्यापारी अपने उद्यम का रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2023 तक करायें और निःशुल्क मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठायें तथा अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग कार्यालय से संपर्क करें।

माटीकला शिल्पकारी प्रशिक्षण हेतु 25 जुलाई तक करें आवेदन – सुष्मिता सिंह

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सुष्मिता सिंह ने अवगत कराया कि ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद में माटीकला कौशल विकास योजना के अंतर्गत 15 दिवसीय शिल्कारी प्रशिक्षण हेतु 22 शिल्पकारियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

उन्होने कहा कि माटीकला कौशल विकास योजना में आर्थिक रूप से निर्बल तथा जिनका जीविकोपार्जन एक मात्र माटीकला व्यवसाय पर ही निर्भर हो, वह इस शिल्पकारी प्रशिक्षण हेतु 25 जुलाई 2023 तक आवेदन जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, हरदोई में जमा करें।

विधायक अयोध्या ने कुंडो के जीर्णोद्धार कार्य का किया निरीक्षण, दंत धवन कुंड व गिरिजा कुंड पर निर्माण कार्य में गुणवत्ता ना पाये जाने पर दी सख्त हिदायत।

अयोध्या– नगर विधायक अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता ने यूपीपीसीएल के अधिकारियों के साथ अयोध्या के जीर्णोद्धार कराए जा रहे पौराणिक कुंडो का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम अयोध्या के दंत धवन कुंड का निरीक्षण करने पहुंचे नगर विधायक को वहां पर निर्माण सामग्री मोरंग में मिट्टी के पाए जाने पर भारी रोष व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और ठेकेदार को सख्त हिदायत दी कि तत्काल ऐसी निम्न दर्जे की घटिया मोरंग को हटा कर उच्च दर्जे की मोरंग का ही प्रयोग किया जाए ताकि निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित ना हो। इसी क्रम में उन्होंने जनौरा स्थित गिरिजा कुंड का भी निरीक्षण किया जहां पर निर्माण कार्य में अनियमितता देखकर उन्होंने सभी को हिदायत देते हुए कहा अगर इसमें किसी भी प्रकार की हीला हवाली या गुणवत्ता के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अपनी तरफ से भी निर्माण कार्यों में और अच्छा प्रदर्शन लाने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से विकास कार्यों का खाका खींच रही है वह प्रशंसनीय है, इसके साथ–साथ पौराणिक महत्व के कुंडो आदि का भी जीर्णोद्धार करा रही है जिससे हमारी भारतीय संस्कृति सदियों तक सुरक्षित रहे। जीर्णोद्धार कार्यों के निरीक्षण के पश्चात श्री गुप्त ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से मिलकर इनके रखरखाव के लिए भी किसी कंपनी या संस्था को लगाने का अनुरोध करूंगा, ताकि यहां पर साफ–सफाई और इनकी देखरेख होती रहे। निरीक्षण के समय उनके साथ यूपीपीसीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर, अधिकारी, जूनियर इंजीनियर व विधायक के साथ रहे जेई सचिन पटेल तथा स्थानीय पार्षद पद प्रत्याशी गौरव सिंह भी मौजूद रहे।

मोटे अनाज के प्रचार प्रसार व बीज वितरण में खूब बरती गई शिथिलता

बुधवार को मवई व रुदौली ब्लॉक में बंटा गया मोटे अनाज का निःशुल्क किट।

रुदौली–अयोध्या। शासन के निर्देश पर बुधवार को मवई व रुदौली ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित कृषि कल्याण केंद्र में विधायक रामचंद्र यादव द्वारा किसानों में मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो का बीज किट वितरित किया गया। सरकार की ओर से वर्ष 2023 का मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है।सरकार ने इस बार के बजट में मोटे अनाज को ष्श्री अन्नष का नाम देते हुए कृषि विभाग के अफसरों को मोटे अनाज की उपज बढ़ाने के लिए बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार व किसानों में निःशुल्क बीज किट वितरण का निर्देश दिया था।लेकिन अयोध्या जिले के तहसील रुदौली में अफसरों की संवेदनहीनता के चलते मोटे अनाज को सरकार के प्रयासों को पंख नही लग पा रहे है।कृषि विभाग रुदौली के एडीओ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभी समय नही बीता है।मोटा अनाज पूरे जुलाई माह बोया जा सकता है।वही कृषि जानकारों का कहना कि 15 जून से 15 जुलाई तक इसकी बुआई हो जानी चाहिए।कृषि कल्याण केंद्र प्रभारी उमाशंकर वर्मा के मुताविक मवई में करीब 101 किसानों को उनके जरूरत के मुताविक बीज रुदौली विधायक रामचंद्र यादव द्वारा वितरित किया गया।वही बीज भंडार प्रभारी भेलसर अनिल कुमार गौड़ ने बताया 66 किसानों में बीज वितरित किया गया। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव, राम नेवल, राज किशोर, राजेश कुमार पाण्डेय, राकेश कुमार ,सुरेश कुमार, सचिन कसौधन , मोहम्मद अबुजर सहित अन्य किसान मौजूद रहे।

25 हजार गाड़ियों का टैक्स नहीं जमा

संवाददाता

लखनऊ। पुरानी गाड़ियों के मालिकों से टैक्स निकालने के लिए परिवहन विभाग ने स्क्रैपिंग नीति के तहत बड़ी छूट देने का ऐलान किया है। जिसमें टैक्स में 75 फीसदी तक की छूट मिल सकती है। मौजूदा समय निजी और प्राइवेट गाड़ियों को मिलाकर करीब 25 हजार गाड़ियां ऐसी है जिनका टैक्स नहीं जमा है। इसमें ज्यादातर गाड़ियां 15 या 20 साल पुरानी है। छूट के अनुसार 20 साल पुराने व्यावसायिक और प्राइवेट वाहनों के स्क्रैप कराने में टैक्स में 75 फीसदी तक की छूट मिलेगी। नए नियम में 15 से 20 साल के बीच पुराने गाड़ियों पर 50 फीसदी और 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर 75 फीसदी की छूट देने का प्रावधान किय गया है। यहां तक स्क्रैपिंग के बाद अगर नई निजी वाहन खरीदा जाता है तो उसमें रोड टैक्स में भी 15 फीसदी और कॉमर्शियल वाहन लेने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी।

मौसम में बदलाव के चलते अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या

संवाददाता

लखनऊ। बारिश के कारण बड़ी संख्या में मरीज संक्रामक रोगों की चपेट में आ रहे हैं। इसका असर अस्पतालों में भारी भीड़ के रूप में देखा जा रहा हैं। लखनऊ के ज्यादातर बड़े अस्पतालों में बुधवार को मरीजों और तीमारदारों की भीड़ उमड़ी। इनमें सबसे ज्यादा मरीज फिजिशियन डॉक्टर के चौम्बर के बाहर दिखे। इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञ और त्वचा रोग विशेषज्ञ के कमरे के बाहर भी लंबी कतारें देखने को मिली। बलरामपुर अस्पताल के अलावा सिविल अस्पताल और लोकबंधु अस्पताल में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे। जिला अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की लाइन लगनी शुरू हो गई। बड़ी संख्या में मरीज ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अलावा दवा काउंटर पर भी दिखें। ज्यादातर मरीजों को पेट से जुड़ी समस्या रही। लोकबंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि अस्पतालों की ओपीडी में हेपेटाइटिस–ए, पीलिया, लिवर में सूजन, टाइफाइड और गैस्ट्रोएंट्राइटिस के 500 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बारिश से बढ़ी गर्मी व उमस से त्वचा से जुड़ी बीमारियों के मरीज ओपीडी में 30 फीसदी बढ़ गए हैं। सिविल अस्पताल के विशेषज्ञ डॉ. एनबी सिंह ने बताया, ओपीडी में सामान्य दिनों के मुकाबले 100 से अधिक मरीज बढ़ गए हैं।

एनडीए की मजबूती में जुटी बीजेपी

संवाददाता

लखनऊ। एनडीए के मुकाबले के लिये अब इंडिया तैयार है। अब 2024 में लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया होगी। एनडीए केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाना चाहता है तो इंडिया इसकी राह रोकने के लिए तैयारी में है। लेकिन कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा ने गठबंधन सहयोगियों के सहारे से पूर्वांचल, अवध व बुंदेलखंड में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है।

हिन्दी सांध्य दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी प्रभुदयाल श्रीवास्तव की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0–7007415808,9628325542,9415034002

RNI संन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R-1

deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायलय होगा।